आकाशवाणी शिमला

26.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1500 बजे

अनुदान

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत असंबद्ध अनुदानों की पहली किस्त के रूप में 67 करोड़ 95 लाख रुपये जारी किए है। इस धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों में स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति ,घरेलू कचरे का प्रबंधन व उपचार, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण कार्य किये जायेगे।

जीएसटी सुधार

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ ले सकते हैं जो 22 सितम्बर से लागू हो गए हैं। जीएसटी परिषद ने पांच प्रतिशत, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय कर संरचना के स्थान पर पांच और 18 प्रतिशत कर संरचना लागू की है। माल और वस्तुओं की व्यापक रेंज पर कर की दर घटने से नागरिकों को अत्यधिक राहत मिली है।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधारों को मंजूरी देते हुए, इसे आम लोगों और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए अधिक सरल और लाभकारी बना दिया है। अब तक लागू होने वाले पांच, बारह, अठारह और अठाईस प्रतिशत की चार स्तरीय संरचना को घटाकर केवल पांच और अठारह प्रतिशत की दो स्तरीय संरचना कर दी गई है। इसके साथ ही तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं जैसे चुनिंदा वस्तुओं पर चालीस प्रतिशत का अतिरिक्त स्लैब लगाया गया है। परिषद का कहना है कि दरों का यह युक्ति–संगतीकरण आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के अन्य चालकों को राहत देगा। नए ढांचे के तहत कई आवश्यक खाद्य पदार्थ, जैसे अति उच्च तापमान वाला दूध, छेना, पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड और चपाती को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की जरूरतें और सस्ती होंगी। कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों जैसे उपकरणों पर जीएसटी बारह से घटाकर पांच कर दिया गया है। वहीं, तीन सौ पच्चास सीसी तक के दो पहिया वाहनों पर जीएसटी अठाईस से घटाकर अठारहा कर दिया गया है, जिससे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों, युवा पेशेवरों और गिग श्रमिकों को सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली निवासी अभय प्रताप ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। ष्मैं अभी अपने लिए जीएसटी दरों में कटौती होने के कारण, जो अठाईस से अठारहा हुआ है, इसलिए बाइक लेने जा रहा हूं इस दिवाली में। सरकार का मैं तहे दिल से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।ष नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बैंकों से आपदा प्रभावितों को ऋणों की किश्त देने में राहत देने का आग्रह किया है। आज शिमला में हुई राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है ऐसे में लोगों के कर्ज वापिस करने की क्षमता प्रभावित हुई है। बैठक में बैंकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपने मुख्य कार्यालयों को इस संबंध में आग्रह करेंगे। मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि ऋणों की अदायगी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो एक सप्ताह के भीतर इस विषय पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट देगी।

राजस्व मामले

प्रदेश सरकार ने राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से अक्तूबर 2023 से अगस्त 2025 तक 4 लाख 33 हजार 2 सौ 42 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि वर्ष 2023 से आरम्भ हुई राजस्व लोक अदालतें अब हर महीने के अंतिम दो दिनों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने मिशन मौड में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों की शुरूआत की है और इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों को जनता का व्यापक समर्थन मिला है।

जयंती

आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें देश प्रदेश में याद किया जा रहा है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ और वे प्रधानमंत्री के रूप में मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा व खाद्य सुरक्षा जैसे अधिकारों के ज़रिए लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जाने जाते है ।

पैंशनर

राज्य पथ परिवहन निगम के लगभग 8 हजार पैंशनरों को इस महीने अभी तक पैंशन नहीं मिली है। हिमाचल पथ परिवहन पैंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने तुरंत पैंशन जारी नहीं की और भविष्य के लिए पैंशन की तारीख तय नहीं की तो निगम के पैंशनर उग्र आंदोलन करेंगे। देवराज ठाकुर ने कहा कि अगस्त महीने में भी 30 तारीख को पैंशन मिली थी और इस महीने भी अभी तक पैंशन का कोई अता–पता नहीं है। उन्होंने कहा कि निगम के पैंशनरों के मैडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा है और एरियर तथा डीए भी लम्बित है। ऐसे में पैंशनरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

————————————————